वित्तीय मदद का ऐलान

ब्रेग्जिट की शर्तों को लेकर भी यूरोपीय संघ के देशों का ब्रिटेन के साथ टकराव बना हुआ है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान यूरोपीय देशों और नाटो सहयोगियों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। बाइडन के लौटने से स्थिति बेहतर हुई है, जिसकी झलक जी-7 मीटिंग में दिखी।

मनोज सिंह।।

दुनिया के सात अमीर लोकतांत्रिक देशों (जी–7) के राष्ट्राध्यक्षों की दो साल में पहली बार ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में आमने–सामने की मीटिंग पूरी हो गई। जो बाइडन इसके जरिये संदेश देना चाहते थे कि अमेरिका फिर से वैश्विक अजेंडा तय करने की अपनी केंद्रीय भूमिका में लौट आया है, जिसे उसने डोनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान गंवा दिया था। कुछ हद तक अमेरिका इसमें सफल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के व्यवहार पर नजर रखने को लेकर जी–7 देशों में आपसी चर्चा पर सहमति बनी।

चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के मुकाबले में जी–7 की ओर से दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए वित्तीय मदद का ऐलान किया गया, जिस पर किसी ठोस पहल में वक्त लगेगा। जी–7 ने चीन में मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचना की और विकासशील–गरीब देशों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए साल भर में 1 अरब वैक्सीन देने पर भी सहमति बनी। संयुक्त बयान में कोरोना महामारी कहां से शुरू हुई, उसकी जांच की बात कही गई। लेकिन चीन के खिलाफ वैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसा कि अमेरिका चाहता था।

चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जर्मनी, इटली और यहां तक कि फ्रांस भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। चीन ने भी कहा कि अब वह दौर नहीं रहा, जब छोटे समूह दुनिया की तकदीर तय किया करते थे। उसका इशारा जी–20 समूह और बहुदेशीय संस्थाओं की ओर था। उधर, जी–7 के अंदर भी संबंध सहज नहीं हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ब्रिटेन और अमेरिका से नाराज हैं।

यूरोपीय संघ में जब कोरोना पीक पर था, तब दोनों देशों ने उसे वैक्सीन के निर्यात को रोक दिया था। ब्रेग्जिट की शर्तों को लेकर भी यूरोपीय संघ के देशों का ब्रिटेन के साथ टकराव बना हुआ है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान यूरोपीय देशों और नाटो सहयोगियों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। बाइडन के लौटने से स्थिति बेहतर हुई है, जिसकी झलक जी–7 मीटिंग में दिखी। लेकिन यह भी दिखा कि अमेरिका के लिए अब पहले जैसे हालात नहीं रह गए, जब वह वैश्विक अजेंडा तय करता था और समूह के बाकी देश उसके पीछे चलते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाइडन इसकी कोशिश छोड़ देंगे। वह चीन और रूस के खिलाफ वैश्विक मोर्चाबंदी में लगे हैं। जी–7 और क्वाड जैसे समूहों का वह इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्वाड में भारत अहम भागीदार है। यह भी याद रखना होगा कि चीन ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनातनी शुरू की, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए नए शीत युद्ध जैसे माहौल में अब जो वैश्विक मोर्चेबंदी हो रही है, उसमें भारत को किसी का मोहरा न बनते हुए अपने हितों का ख्याल रखना होगा।

यज्ञ

अशोक वोहरा।

पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है, यही पुण्य भी है। यज्ञ के प्रमुख पांच प्रकार हैं– ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेदपाठ करने से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। देवयज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से सम्पन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है।

पितृयज्ञ को श्राद्धकर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और सन्तानोत्पत्ति से सम्पन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न–जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना।

संपादकीय

दुष्ट राष्ट्र की छवि

दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की इस दादागीरी को निरस्त करने के मकसद से भारत ने अन्य ताकतवर देशों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा अध्यक्षता अवधि में समुद्री सुरक्षा पर विशेष बैठक का आयोजन किया। जिस तरह चीन के दोस्त रूस ने भी इस बैठक में पारित साझा प्रस्ताव में भारतीय मसौदे का समर्थन किया, उससे चीन को समझ लेना चाहिए कि उसकी विस्तारवादी नीतियों से उसके साथी देश भी चिंतित हैं। दक्षिण चीन सागर जैसे समृद्ध इलाके पर चीन की ललचाई निगाह इसलिए पड़ी है कि यह दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है, जहां से दुनिया के व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है। 36 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में 900 ट्रिलियन घन फीट प्राकृतिक गैस और सात अरब बैरल खनिज तेल है। इसके अलावा इस इलाके से दुनिया का कुल 12 प्रतिशत मछली व्यापार होता है। इस विशाल प्राकृतिक संपदा पर एकाधिकार जमाने के लिए ही चीन ने वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ प्रादेशिक इलाकाई विवाद छेड़ रखा है और इस इलाके में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर अपने समुद्री इलाके का कानूनी विस्तार करने की रणनीति अपना रहा है। इससे दुनिया में तनाव का माहौल पैदा होने लगा है, जिससे चीन की छवि एक दुष्ट राष्ट्र जैसी बनती जा रही है।

दक्षिण चीन सागर में सैनिक या व्यापारिक पोतों की खुली आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ही भारत हिंद-प्रशांत इलाके की अन्य बड़ी नौसैनिक ताकतों के साथ खड़े होकर चीन को ललकार रहा है, लेकिन चीन की भी हेकड़ी बढ़ती जा रही है।

नाम में क्या रखा है

रंजीत कुमार।।

यह महज संयोग नहीं कि जब भारतीय नौसेना के चार सबसे ताकतवर युद्धपोत दक्षिण चीन सागर के मुहाने पर दस्तक दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में संयुक्त राष्ट्र के प्रभावशाली सदस्यों ने एक स्वर से चीन को आगाह किया कि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करे। इन दिनों दक्षिण चीन सागर में विनाशकारी मिसाइलों से लैस चार बड़े भारतीय युद्धपोत विचरण कर रहे हैं, जिनकी योजना अगले दो महीनों में दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय देशों वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास करने की है। इसके बाद ये पोत पश्चिमी प्रशांत में जाकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास भी करेंगे। चीनी की समुद्री सीमा के करीब भारतीय नौसैना अन्य देशों के साथ इस तरह अपना शक्ति प्रदर्शन पिछले कई सालों से कर रही है।

दक्षिण चीन सागर में सैनिक या व्यापारिक पोतों की खुली आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ही भारत हिंद–प्रशांत इलाके की अन्य बड़ी नौसैनिक ताकतों के साथ खड़े होकर चीन को ललकार रहा है, लेकिन चीन की भी हेकड़ी बढ़ती जा रही है। नतीजतन, दक्षिण चीन सागर में तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। दक्षिण चीन

सागर का चीन पर नामकरण उसी तरह किया गया है, जिस तरह भारत के निकट के सागरीय इलाके को हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहा जाता है। जिस तरह इंडियन ओशन भारत का नहीं है, उसी तरह दक्षिण चीन सागर भी चीन का नहीं है लेकिन चीन ने इस इलाके में एक काल्पनिक नाइन–डैश लाइन खींचकर उसके अंदर आने वाले सभी समुद्री इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। इस इलाके में विदेशी पोतों के विचरण करने पर फिलहाल तो चीन केवल एतराज ही करता है, लेकिन यदि वह अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो गया तो भविष्य में इधर से किसी पोत के गुजरने पर रोक–टोक भी कर सकता है। भारत सहित दुनिया की बड़ी नौसैनिक ताकतों ने चीन के इन दावों को नजरअंदाज किया है। वे अक्सर युद्धपोत वहां भेजकर चीन को आगाह करते रहते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाका है, जहां संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (अनक्लास) के तहत सभी विदेशी पोतों को खुली आवाजाही की छूट है। यही जताने के लिए पिछले 2 अगस्त को जर्मनी ने दो दशक बाद पहली बार अपना एक फ्रिगेट दक्षिण चीन सागर के इलाके में तैनात किया। इसके पहले ब्रिटेन ने अपना नया विमानवाहक पोत एलिजाबेथ दक्षिण चीन सागर के इलाके में भेज कर चीन को चिढ़ाया था। अमेरिका ने भी पिछले महीने अपने विमानवाहक पोतों का विशाल बेड़ा वहां भेजा था। जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत भी इस इलाके में भेजे जाते रहे हैं।

इन विदेशी पोतों के जवाब में चीन ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में अपने कई युद्धपोतों को उतारकर एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया। ध्यान रहे, पूर्वी चीन सागर में भी चीन ने जापान के साथ द्वीपों के स्वामित्व को लेकर विवाद छेड़ा हुआ है। ठीक इन्हीं दिनों जब भारतीय युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया तो चीन ने अप्रत्यक्ष चेतावनी भरे लहजे में उम्मीद जताई कि कोई देश शांति भंग करने की कार्रवाई नहीं करेगा।

अष्टयोग-5049

	3		4	5		
2	30	7	31		34	2
1			3		7	
	28	6	31	6	39	3
4		1			5	7
3	30		32	7	34	
	5		6		2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5048 का हल

2	3	6	4	1	7	5
7	30	2	25	2	34	4
4	5	1	3	6	7	2
6	28	5	35	3	39	6
1	2	4	6	7	5	3
5	30	3	42	5	34	7
3	5	7	6	4	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

बड़ी ताकतों के बीच जोर आजमाइश

मोहन। साफ है कि इस इलाके को लेकर चीन और अन्य क्षेत्रीय व बड़ी ताकतों के बीच जोर आजमाइश तेज होने लगी है। यदि दक्षिण चीन सागर के इलाके पर चीन के स्वामित्व के दावे को आज खारिज नहीं किया गया तो बाद में वह न केवल भारत बल्कि सभी विदेशी पोतों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है। इस इलाके का अंतरराष्ट्रीय आवागमन के लिए खुला रहना इसलिए भी अहम है क्योंकि व्यापारिक पोतों के जरिए भारत का आधे से अधिक आयात–निर्यात इसी रास्ते से होता है। यदि दक्षिण चीन सागर के इलाके पर चीन के अधिकार के दावे को आज गैरकानूनी नहीं ठहराया गया तो वह बाद में इस इलाके से सैनिक पोतों की आवाजाही को पूरी तरह रोकने का अधिकार हासिल कर सकता है और व्यापारिक पोतों पर टैक्स लगाने का अधिकार भी ले सकता है। भारत के लिए विशेष चिंता की बात इसलिए है क्योंकि तनाव की स्थिति में चीन भारत के इस मार्ग से होने वाले आधे से अधिक व्यापार पर रोक लगा कर उसकी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा सकता है।